

आर. रतिलाल एंड कंपनी

बनाम

नेशनल सिक्योरिटी एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(ए. के. सरकार, जे. सी. शाह और रघुबर दयाल, जे. जे)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (1899 का द्वितीय), धारा 35 अनुसूची-1 अनुच्छेद 47 अग्नि बीमा के कवर का बिना स्टाम्प वाला पत्र-कब साक्ष्य में ग्राह्य हैं।

अपीलार्थी ने अग्नि से बीमित माल के विनाश के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की वसूली के लिए प्रत्यर्थी द्वारा जारी उसी प्रकार के बीमा के संबंध में अग्नि बीमा की विधिवत पूर्ण पॉलिसी और कवर के एक अनस्टैम्पड पत्र पर वाद दायर किया। प्रत्यर्थी ने पॉलिसी पर दायित्व स्वीकार किया लेकिन कवर पत्र के संबंध में उसने तर्क दिया कि पत्र स्टाम्प के अभाव में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था।

अभिनिधारित: सरकार और शाह जे. जे. (i) बीमा पत्र में निस्संदेह बीमा का अनुबंध होता है लेकिन यह बीमा पॉलिसी नहीं है और स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ii) स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1 के अनु० 47 में सामान्य छूट की शर्त यह है कि कवर-पत्र को शुल्क से केवल तभी छूट नहीं दी जाती है जब इसका उपयोग उसमें उल्लिखित पॉलिसी के वितरण को बाध्य करने के लिए किया जाता है। यदि इसका उपयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है तो इसमें छूट नहीं है। जब इसे इतनी छूट नहीं दी जाती है तो यह स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के तहत शुल्क प्रभार्य लिखत हैं और अपेक्षित शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है।

रघुबर दयाल जे. (असहमति जताते हुए): धारा 35 के अनुसार दायित्व पत्रों पर निष्पादन के वक्त आवश्यक स्टाम्प होना चाहिए और यह कि बाद में आवरण पत्र पर आवश्यक स्टाम्प लगाने से यह एक ऐसा दस्तावेज नहीं बन जाएगा जिसका उपयोग दावे के आधार सहित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सके। सामान्य अपवाद के परंतुक का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि दायित्व पत्र के निष्पादन के बाद कोई भी पक्ष उस पर केवल अपेक्षित स्टाम्प लगा सकता है और उसके बाद किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी दावे को लागू करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। नारायणन चेट्टियार बनाम करुप्पाथन, आई. एल. आर. 3 मद्रास 251.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 382/1961

मूल डिक्री सं० 144/1958 की अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24 मई, 1960 और डिक्री के विरुद्ध।

बी. के. भट्टाचारजी, डी. के. डे और एस. एन. मुखर्जी जी, अपीलार्थी के लिए।

एन. सी. चटर्जी और डी. एन. मुखर्जी -प्रत्यर्थी।

16 दिसंबर, 1963। निर्णय ए. के. सरकार और जे. सी. शाह जे. का निर्णय सरकार जे द्वारा दिया गया था, रघुबर दयाल जे. ने एक असहमतिपूर्ण राय दी।

न्यायाधिपति सरकार.- अपीलकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में 15 मार्च, 1951 की अग्नि बीमा की विधिवत पूर्ण की गई पॉलिसी संख्या 26625, और 5 नवंबर, 1951 के एक बिना स्टाम्प लगे दायित्व पत्रपर प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए उसी प्रकार के बीमा के संबंध में, आग से बीमित वस्तुओं के नष्ट होने के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मुकदमा दायर किया। प्रत्यर्थी ने पॉलिसी संख्या 26625 पर दायित्व स्वीकार किया लेकिन दायित्व पत्र के संबंध में यह तर्क दिया कि स्टाम्प के अभाव में पत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं था। चूँकि इसने किसी अन्य आधार पर दायित्व पत्र या पॉलिसी पर दायित्व का विरोध नहीं किया, इस अपील में एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या दायित्व पत्र को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह प्रश्न स्टाम्प

अधिनियम, 1899 के कुछ प्रावधानों पर निर्भर करता है, जिसका संदर्भ उचित समय पर दिया जाएगा।

दायित्व पत्र जिस पर 'अंतरिम सुरक्षा नोट' का विवरण दिया गया है प्रदान करता है कि अपीलकर्ता ने "आग के खिलाफ बीमा कराने का प्रस्ताव रखा है और उस पर टैरिफ प्रीमियम का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, संपत्ति को नीचे निर्दिष्ट तरीके से 1,00,000 रुपये की सीमा तक बीमाकृत रखा गया है। "इसके बाद सामान का विवरण और यह बयान दिया गया कि कवर किए जाने वाले जोखिम 5 नवंबर, 1951 से बारह महीनों के लिए उक्त पॉलिसी नंबर 26625 के अनुसार होंगे। इसके बाद यह कहा गया, "सुरक्षा तीस दिन के लिए लागू है..... या जब तक कंपनी की पॉलिसी तैयार नहीं हो जाती, जब तक कि बीमा अस्वीकार न हो जाए" जिस आग पर दावा आधारित है, वह 5 नवंबर 1951 की रात या अगले दिन सुबह के शुरुआती घंटों में लगी थी। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता ने दायित्व पत्र पर देय सभी प्रीमियम का भुगतान करने की पेशकश की।

इस स्तर पर स्टाम्प अधिनियम के दो प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगा और वे हैं धारा 35 और अनुसूची 1 में अनुच्छेद 47 धारा 35 प्रदान करती है, "शुल्क प्रभार्य कोई भी लिखत किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे लिखत पर

विधिवत स्टाम्प न लगाई गई हो: बशर्ते कि - (ए) ऐसा कोई भी लिखत शुल्क प्रभार्य लिखत न हो। केवल दस नए पैसे से अधिक, या विनिमय का बिल या वचन पत्र, सभी अपवादों के अधीन, उस शुल्क के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा जिसके साथ वह वसूलनीय है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पत्र कवर का एक "साधन" है। अधिनियम की अनुसूची 1 विभिन्न लिखतों पर देय शुल्क को निर्दिष्ट करती है। अनुसूची 1 का अनुच्छेद 47 बीमा की विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों पर लगने वाले कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। इस अनुच्छेद का भाग ख अग्नि बीमा पॉलिसियों से संबंधित है और विभिन्न राशियों के लिए अग्नि बीमा की विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों के संबंध में देय विभिन्न शुल्क निर्दिष्ट करती है, इस अनुच्छेद के तहत बीमा की पॉलिसी पर लगने वाला न्यूनतम शुल्क पचास नए पैसे है। अब इस अनुच्छेद के अंत में एक सामान्य छूट है जो इन शब्दों में है :

"सामान्य छूट

बीमा की पॉलिसी जारी करने के लिए आवरण अथवा वचनबद्धता पत्र -इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे वचनबद्धता पत्र में जब तक ऐसी पॉलिसी के लिए इस

अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प नहीं लगाए जाएं, इसके अन्तर्गत कोई दावा नहीं किया जाएगा और न ही इसमें उल्लिखित पॉलिसी की सुपुर्दगी को बाध्य करने को छोड़कर यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपलब्ध होगी।”

हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 47 में सामान्य छूट के परंतुक में 'ऐसी पॉलिसी' शब्द हैं जो उस प्रकार की पॉलिसी को संदर्भित करता है जिसके साथ छूट के पहले भाग में उल्लिखित पॉलिसी जारी करने के लिए एक पत्र या वचनबद्ध का संबंध है। इसलिए, वर्तमान मामले में, "ऐसी पॉलिसी" शब्द अग्नि बीमा की पॉलिसी को इंगित करेंगे। इस पर कोई विवाद प्रकट नहीं होता है।

अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि दायित्व पत्र वास्तव में बीमा की एक पॉलिसी है और अग्नि बीमा की पॉलिसी पर लगने वाले शुल्क और अधिनियम की धारा 35 के परन्तुक (अ) के प्रावधानों के तहत जुर्माने के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। इसके बाद यह कहा गया कि भले ही यह बीमा की पॉलिसी न हो, बल्कि केवल दायित्व पत्र हो, फिर भी यह उस धारा के तहत शुल्क प्रभार्य साधन के रूप में साक्ष्य में स्वीकार्य होगा क्योंकि यह न तो विनिमय का बिल था, न ही वचन पत्र और न ही

एक लिखत जिस पर दस नये पैसे से अधिक का शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने माना कि यह लिखत दायित्व पत्र नहीं था बल्कि यह वास्तव में बीमा की एक पॉलिसी थी क्योंकि इसमें बीमा का अनुबंध शामिल था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि यह दृष्टिकोण सही है, तो शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर लिखत धारा 35 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य होगी। उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ, विद्वान विचारण न्यायाधीश के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ थी और, हमारा मानना है कि, इसमें अपीलीय पीठ सही थी। दायित्व पत्र में बीमा का अनुबंध होता है, इस तथ्य के कारण इसे बीमा की पॉलिसी नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि अपीलीय पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने ठीक ही बताया है, दायित्व पत्र को अनुच्छेद 47 में निर्दिष्ट शुल्क के दायित्व से सामान्य छूट दी गई थी, अर्थात्, इसे उस शुल्क से छूट दी गई थी जो, लेकिन ऐसी छूट के लिए, उस अनुच्छेद के तहत उस पर देय होती। अब अनुच्छेद 47 के तहत, बीमा की विभिन्न पॉलिसियों पर शुल्क देय था। इसका मतलब यह होगा कि यदि छूट नहीं दी गई होती तो दायित्व पत्र बीमा की पॉलिसी के रूप में शुल्क के लिए उत्तरदायी होता। इसलिए, दायित्व पत्र में बीमा का अनुबंध शामिल होना चाहिए अन्यथा अनुच्छेद 47 के तहत शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन इससे यह बीमा की पॉलिसी नहीं बन गई,

क्योंकि तब छूट और अनुच्छेद एक-दूसरे के साथ टकराव में होती। हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि 'कवर' शब्द स्वयं इंगित करता है कि संपत्ति को कुछ जोखिमों के खिलाफ बीमाकृत या कवर किया गया है।

तो फिर दायित्व पत्र क्या है? इसे बीमा पॉलिसी से कैसे अलग किया जाए? अधिनियम में इसकी या 'बीमा की पॉलिसी जारी करने के दायित्व' की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन शर्तें व्यापार में अच्छी तरह से जानी जाती हैं। यह अधिनियम व्यवसायियों और उनके परिचित व्यापारिक दस्तावेजों से संबंधित है। यह कहा जा सकता है कि दायित्व पत्र में निस्संदेह बीमा का अनुबंध होता है लेकिन व्यापार में उस शब्द की आम समझ में यह बीमा की पॉलिसी नहीं है। यह सर्वविदित है कि आग के जोखिम के खिलाफ बीमा प्राप्त करने के लिए बीमित व्यक्ति को पहले बीमाकर्ता को एक प्रस्ताव भेजना होता है और फिर बीमाकर्ता यह पूछताछ करने में थोड़ा समय लेता है कि क्या वह प्रस्ताव स्वीकार करेगा और दायित्व लेगा या नहीं। जोखिम को कवर करने की कोई पॉलिसी वह तभी जारी करता है जब वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा करना एक विवेकपूर्ण व्यावसायिक प्रस्ताव होगा। हालाँकि, व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुभव से पता चला है कि जब बीमाकर्ता पूछताछ करता है तब अंतरिम अवधि के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा आवश्यक है। यह सुरक्षा 'दायित्व पत्र' के नाम से दी जाती है। यह स्पष्ट रूप से एक अनुबंध है जो अपनी तिथि के बीच

की अवधि के लिए बीमा प्रदान करता है और पॉलिसी तैयार होने और वितरित होने तक, यदि कोई अंततः जारी किया जाता है या अन्यथा इसमें उल्लिखित तिथि तक, जैसा कि जारी किए गए अंतरिम सुरक्षा नोट में तीस दिनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। इस मामले में: "द सिटीजन्स इंश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम विलियम पार्सन्स" देखने योग्य है। हमारा मानना है कि वर्तमान अंतरिम संरक्षण नोट उन शर्तों को पूरा करता है जो इसे इस अर्थ में एक दायित्व पत्र बना देगा। यह तीस दिनों की अवधि या पॉलिसी जारी होने की तारीख तक की अवधि के लिए सुरक्षा देता है। हमें ऐसा लगता है कि पॉलिसी जारी करने की प्रतिबद्धता का मतलब कमोबेश दायित्व पत्र के समान ही है। इसलिए, दायित्व पत्र को धारा 35 के तहत बीमा की एक पॉलिसी के रूप में साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अगला सवाल यह है कि क्या दायित्व पत्र स्वयं अधिनियम के तहत एक शुल्क प्रभार्य लिखत है। यह विवादित नहीं है कि यदि यह इतना प्रभार्य नहीं है, तो इसे धारा 35 के तहत बाद में शुल्क और जुर्माने का भुगतान करके साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब धारा 3 उन लिखतों को निर्दिष्ट करता है जो अधिनियम के तहत शुल्क प्रभार्य हैं। इसमें कहा गया है, "इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची 1 में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित लिखतें पर उस अनुसूची में इंगित

राशि के शुल्क के साथ क्रमशः उचित शुल्क लगाया जाएगा, अर्थात्, - (ए) उस अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लिखत जो..... जुलाई 1899 (1 जुलाई, 1899 वह तारीख है जिस दिन यह अधिनियम लागू हुआ) के पहले दिन या उसके बाद भारत में निष्पादित किया जाता है।

अब प्रत्यर्थी का तर्क यह है कि दायित्व पत्र एक शुल्क प्रभार्य लिखत नहीं है क्योंकि अनुसूची का अनुच्छेद 47 में सामान्य छूट इसे ऐसे शुल्क से छूट देता है। इस तर्क को उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने स्वीकार कर लिया, जिन्होंने बताया "यह महत्वपूर्ण है कि इस्तेमाल किए गए शब्दों का मतलब यह नहीं है कि ऐसा पत्र शुल्क प्रभार्य है। इस्तेमाल किए गए शब्द 'ऐसी पॉलिसी के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प लगाते हैं'। उचित व्याख्या करने पर इसका मतलब यह है कि इस तरह के दायित्व पत्र पर अधिनियम के तहत शुल्क नहीं लगता है, लेकिन यदि यह बीमा की पॉलिसी के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प को धारण करता है, तो यह अपनी असमर्थता को दूर कर देगा और एक सक्षम दस्तावेज बन जाएगा, जिस पर नुकसान का दावा किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा, "चूंकि इस तरह के दायित्व पत्र के लिए कोई स्टाम्प तय नहीं किया गया है, जो शुल्क प्रभार्य दस्तावेज नहीं है, कानून महत्वपूर्ण शब्दों या 'स्टाम्प धारण करने' का उपयोग करता है और यह

कहकर दर को इंगित करता है कि स्टॉप के लिए समान होना चाहिए ऐसा दायित्व पत्र जो अधिनियम के तहत बीमा पॉलिसी के लिए निर्धारित है। इस न्यायालय में प्रत्यर्थी की ओर से श्री चटर्जी ने भी यही तर्क दिया।

हम उस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं जिसे उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ का समर्थन मिला। मामला दो तरह से रखा गया. पहला यह था कि एक लिखत जिसे अनुसूची 1 द्वारा शुल्क से छूट दी गई है, उस पर धारा 3 के तहत शुल्क नहीं लगाया जाएगा और इसमें दायित्व पत्र को स्पष्ट रूप से छूट दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कि यदि किसी लिखत को अनुसूची द्वारा शुल्क से छूट दी गई है, तो उस पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि दायित्व पत्र को सभी उद्देश्यों के लिए सामान्य छूट द्वारा शुल्क से छूट दी गई है। हमारा मानना है कि सामान्य छूट खंड का उचित निर्माण यह है कि छूट केवल तभी लागू होती है जब दायित्व पत्र का उपयोग इसमें उल्लिखित पॉलिसी की वितरण को बाध्य करने के लिए किया जाता है। अगर इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसे छूट नहीं मिलती है, इसीलिए प्रावधान में एक परन्तुक नियोजित किया गया है और इसका प्रभाव अन्य सभी मामलों में छूट से पत्र को बाहर करना है। यदि इसे छूट से बाहर कर दिया जाता है, तो निस्संदेह, वर्तमान तर्क विफल हो जाता है। हम यह देखने में असमर्थ हैं कि कैसे कहा जा सकता है कि दायित्व पत्र

को सभी उद्देश्यों के लिए छूट दी गई है, यदि इसके तहत कुछ चीजों का दावा केवल इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि उस पर कोई स्टाम्प नहीं है। यदि इसे सभी उद्देश्यों के लिए छूट दी जाती, तो यह बिना स्टाम्प के भी पूरी तरह से लागू होता। जब दायित्व पत्र पर स्टाम्प नहीं लगाई जाती है, तो पॉलिसी के वितरण के अलावा इसके तहत कुछ भी दावा योग्य नहीं होता है। हालाँकि, यदि उस पर उपयुक्त पॉलिसी के लिए निर्धारित स्टाम्प लगा है, तो उसके तहत दावा किया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि यदि किसी लिखत पर स्टाम्प है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क का दायित्व आ गया है; फिर इसे छूट नहीं दी गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दायित्व पत्र को सभी मामलों में शुल्क से छूट दी गई है। जब इसे छूट नहीं दी जाती है, तो यह एक शुल्क प्रभार्य लिखत है।

जिस अन्य तरीके से विवाद प्रस्तुत किया गया वह 'इस अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प लगाता है' शब्दों के उपयोग पर आधारित है। यह कहा गया था कि यदि किसी लिखत पर स्टाम्प लगाया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाता है। हम यह देखने में पूरी तरह से असमर्थ हैं कि कोई लिखत अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प कैसे धारण कर सकता है जब तक कि यह अधिनियम के तहत शुल्क प्रभार्य न हो क्योंकि अधिनियम केवल इसके तहत शुल्क प्रभार्य लिखतों से संबंधित है। इस तर्क की सराहना करना मुश्किल है कि 'ऐसी पॉलिसी के लिए इस

अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प लगाता है' शब्दों के उपयोग से तात्पर्य केवल शुल्क की राशि को इंगित करने से था। इसमें कोई संदेह नहीं कि दर तो है, लेकिन लिखत पर उस दर की स्टाम्प लगी होनी चाहिए। अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी लिखत पर स्टांप कैसे लगाया जाएगा। धारा 17 कहती है कि शुल्क प्रभार्य सभी लिखतों पर निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय स्टाम्प लगाई जाएगी। यदि दायित्व पत्र शुल्क के अधीन नहीं है, लेकिन उस पर केवल एक स्टाम्प लगी होनी चाहिए, जैसा कि प्रत्यर्थी का तर्क है, धारा 17 इस पर लागू नहीं होगी। तब ऐसे लिखत को, जिस पर शुल्क नहीं लगता है, लेकिन जिस पर एक निश्चित स्टाम्प लगाना आवश्यक है, उस स्टाम्प को किसी भी समय उस पर लगाने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि जहां किसी लिखत पर केवल स्टाम्प लगाना होता है, वहां लिखत प्रस्तुत करने से पहले सुनवाई के समय भी स्टाम्प लगाई जा सकती है। निःसंदेह, इससे प्रत्यर्थी को बिल्कुल भी सहायता नहीं मिलेगी और हमारे विचार से, अधिनियम में एक विसंगति उत्पन्न होगी जो 'स्टाम्प धारण करता है' शब्दों पर अप्राकृतिक निर्माण करने का परिणाम होगा। हमें लगता है कि 'स्टांप धारण करता है' शब्दों के इस्तेमाल से विधायिका का इरादा यह बताना था कि किसी पॉलिसी की अनिवार्य डिलीवरी को छोड़कर सभी मामलों में दायित्व पत्र पर शुल्क लगाया जाएगा।

इसलिए, हमारी राय में, दायित्व पत्र अधिनियम के तहत एक शुल्क प्रभार्य लिखत है और स्टाम्प अधिनियम धारा 35 के तहत आवश्यक शुल्क और दंड के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार्य है। स्टाम्प अधिनियम के रूप में यह न तो दस नए पैसे से अधिक शुल्क प्रभार्य एक लिखत है और न ही विनिमय का बिल या एक वचन पत्र है।

हमें ऐसा लगता है, हालांकि हम इस पर अपना निर्णय आधारित नहीं करते हैं, कि छूट देने का विचार पहली बार में शुल्क के भुगतान से दायित्व पत्र का उद्देश्य एक ही बीमा पर दो बार शुल्क के भुगतान की कठिनाई से बचना था, दायित्व पत्र के बाद जारी की गई पॉलिसी के लिए दायित्व पत्र के समय से ही माल का बीमा करना होता था कि उनका बीमा किया और पॉलिसी पर स्टाम्प लगानी पड़ी। यदि पॉलिसी ने दायित्व पत्र द्वारा बीमा की समाप्ति के बाद की तारीख से माल का बीमा किया है, तो बाद वाला बीमा की एक स्वतंत्र पॉलिसी होगी, जो कम समय के लिए हो सकती है; तब यह अंतरिम कवर नहीं होगा और इसलिए, दायित्व पत्र बिल्कुल भी नहीं होगा। यह भी कहा जा सकता है कि बहुत कम मामलों में दायित्व पत्र को बीमा के रूप में लागू करना आवश्यक होगा क्योंकि कई मामलों में इसके द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान आग लगने की संभावना नहीं है।

अब हमें यह बताना होगा कि अपीलकर्ता ने धारा 35 के अनुसार आवश्यक शुल्क और जुर्माना का भुगतान किया था। साक्ष्य में दायित्व पत्र की स्वीकार्यता पर अब कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता के दावे के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा किया गया एकमात्र बचाव विफल हो जाता है और ऐसे में अपील सफल होनी चाहिए।

हालाँकि, हम यह देखना चाहते हैं कि इस निर्णय में हमने केवल अग्नि बीमा से संबंधित दायित्व पत्र और अनुसूची 1 के अनुच्छेद 47 में सामान्य छूट में परन्तुक की व्याख्या पर हमारी टिप्पणी उसी सन्दर्भ में की गई है। क्या वे टिप्पणियाँ बीमा की अन्य किस्मों से संबंधित दायित्व पत्र के मामले में लागू होंगी या नहीं, यह हमारे विचार का विषय नहीं है और इस प्रश्न पर हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है।

हम इन कारणों से अपील की अनुमति देंगे और वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में 93,628/81 रुपये के लिए और विद्वान विचारण न्यायाधीश के फैसले की तारीख से छह प्रतिशत ब्याज सहित डिक्री पारित करेंगे।

रघुबर दयाल जे.-में इस बात से सहमत हूँ कि अंतरिम सुरक्षा नोट बीमा की पॉलिसी के बराबर नहीं है और यह बीमा की पॉलिसी जारी करने के लिए कवर या अनुबंध पत्र है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बाद भारतीय स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 35 में प्रावधान (ए) के मद्देनजर इस पर स्टाम्प लगाई जा सकती है

अंतरिम संरक्षण नोट, एक दायित्व पत्र होने के नाते, अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 47 के सामान्य अपवाद के तहत स्टांप शुल्क से छूट दी गई है। इसका उपयोग किसी दावे को आधार बनाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए तभी किया जा सकता है, जब उस पर पॉलिसी के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टांप लगा हो, जिसे दायित्व पत्र के अनुसरण में जारी किया जाना है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा धारा 35 के तहत आवश्यक शुल्क और जुर्माने का भुगतान करने पर इस दायित्व पत्र को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम के धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है, यह उन दस्तावेजों पर लागू नहीं थे जिन पर अधिनियम के तहत शुल्क नहीं लगाया गया था। अपीलकर्ता के लिए इस दृष्टिकोण की सत्यता को चुनौती दी गई है।

परंतुक सहित सामान्य अपवाद के अनुसार

सामान्य छूट- "बीमा की पॉलिसी जारी करने के लिए आवरण अथवा वचनबद्धता पत्र -इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे वचनबद्धता पत्र में जब तक ऐसी पॉलिसी के लिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प नहीं लगाए जाएं, इसके अन्तर्गत कोई दावा नहीं किया जाएगा और न ही इसमें उल्लिखित पॉलिसी की सुपुर्दगी को बाध्य करने को छोड़कर यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपलब्ध होगी।

अधिनियम की धारा 35, (अ) परन्तुक के अलावा अन्य परन्तुक को हटाकर है:

"सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य आदि में अग्राह्य हैं- शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है किसी व्यक्ति द्वारा जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जाएगी:

परन्तु..

(क) कोई ऐसी लिखत ऐसे मुल्क के जिससे वह प्रभार्य है, अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ पांच रुपए की शास्ति अथवा जब उसके उचित शुल्क या कमी वाले भाग के दस गुनी रकम, पांच रुपए से अधिक हो तब ऐसे शुल्क या भाग के दस गुने के बराबर राशि दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

यह स्पष्ट है कि बीमा की पॉलिसी जारी करने के लिए बिना स्टाम्प लगा दायित्व पत्र या अनुबंध का उपयोग केवल उसमें उल्लिखित पॉलिसी की डिलीवरी को बाध्य करने के लिए किया जा सकता है, और न तो

इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और न ही इस पर कोई दावा आधारित किया जा सकता है। दावा उस पर आधारित हो सकता है यदि उस पर दायित्व पत्र या वचनबद्ध के पत्र द्वारा विचारित पॉलिसी के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प लगी हो। सवाल यह है कि क्या प्रावधान पॉलिसी के निष्पादन के समय निर्धारित स्टाम्प को कवर करने के लिए दायित्व पत्र पर विचार करता है या एक दायित्व पत्र ले सकता है जिस पर इसके निष्पादन के समय स्टाम्प नहीं लगी है लेकिन बाद में उस पर स्टाम्प लगाई जाती है कोई भी व्यक्ति इस पर स्टाम्प लगाने या अधिनियम के तहत किसी भी आदेश के तहत रुचि रखता है। मेरी राय है कि यह अपेक्षा करता है की निष्पादन के समय दायित्व पत्र पर आवश्यक स्टाम्प लगाने के लिए दायित्व पत्र अपेक्षा करता है और बाद में बिना स्टाम्प लगे दायित्व पत्र पर अपेक्षित टिकट लगाने से यह एक दस्तावेज नहीं बन जाएगा जिसका उपयोग एक दावे के आधार सहित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

अधिनियम के विभिन्न प्रावधान दस्तावेज पर बाद में स्टाम्प लगाने का प्रावधान केवल तभी करते हैं जब वह दस्तावेज धारा 3 के प्रावधानों के तहत शुल्क प्रभार्य हो। अधिनियम स्वाभाविक रूप से, दस्तावेजों के बाद के स्टाम्प के आदेशों से निपट नहीं सकता था, जो निष्पादन के समय स्टाम्प शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। वे बिना किसी स्टाम्प शुल्क के अच्छे वैध

दस्तावेज हैं और इसलिए भविष्य में न्यायालय या किसी सार्वजनिक अधिकारी के आदेश के तहत उन पर स्टाम्प लगाए जाने के बारे में कोई सवाल नहीं उठ सकता है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि कई धाराएं बाद में घाटा शुल्क और जुर्माना वसूलने से भी संबंधित हैं। किसी दस्तावेज पर स्टाम्प न होने पर किसी जुर्माने पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उस पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है।

नारायणन चेट्टी बनाम करुप्पाथन¹ में यह प्रासंगिक रूप से टिप्पणी की गई है:

"मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज के स्वीकारोक्ति पर प्रावधान के तहत अधिकृत जुर्माना लगाने का अर्थ है, निष्पादन के समय उचित स्टाम्प लगाने में विफल रहने पर उपेक्षा के लिए सजा... जुर्माना लगाने से पता चलता है कि निष्पादन की तारीख वह है जिसे 'प्रभार्य' शब्द के उपयोग में माना जाता है, और इसलिए प्रभार्य का मतलब 1879 के अधिनियम के तहत प्रभार्य नहीं है, लेकिन उस तारीख को लागू कार्यान्वयन अधिनियम के तहत प्रभार्य है।

¹I.L.R. 3 एमएडी. 251,253

इस मामले में व्यक्त दृष्टिकोण की पूर्ण पीठ ने अधिनियम की धारा 46 के तहत राजस्व बोर्ड से मद्रास उच्च न्यायालय के संदर्भ में पुष्टि की थी।

धारा 35 के प्रावधान ऐसे लिखतों पर लागू होते हैं जो शुल्क प्रभार्य थे। ऐसे दस्तावेजों पर, यदि ठीक से स्टाम्प नहीं लगाई गई हो, तो उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता था, न ही उन पर कार्रवाई की जा सकती थी, किसी व्यक्ति या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित किया जा सकता था। कुछ लिखत जिन पर विधिवत स्टाम्प नहीं लगी है, उन्हें साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है यदि वे धारा के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। इस धारा के प्रावधान उन लिखतों पर लागू नहीं होंगे जिन पर शुल्क नहीं लगता है।

धारा 2(6) के अनुसार 'प्रभार्य' का अर्थ है, "प्रभार्य" से वहां जहां कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई किसी लिखत को लागू है, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य अभिप्रेत है, तथा वहां जहां कि वह किसी अन्य लिखत को लागू है उस समय, जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई थी या वहां जहां कि लिखत कई व्यक्तियों द्वारा विभिन्न समयों पर निष्पादित की गई थी उस समय, जब वह प्रथम बार निष्पादित की गई थी, भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य अभिप्रेत है।

अधिनियम की धारा 3 प्रदान करती है कि अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची 1 में निहित छूटों के अधीन, इसके खंडों में उल्लिखित लिखत (ए), (बी) और (सी) उस अनुसूची में इंगित राशि के शुल्क के साथ उचित शुल्क के रूप में प्रभार्य होंगे। इसका मतलब यह है कि जिन लिखतों को अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत छूट दी गई है, उन्हें शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं कहा जा सकता है, भले ही छूट के अभाव में वे लिखत अनुसूची 1 के किसी भी लेख के अंतर्गत आते हों। बीमा की एक पॉलिसी अनुसूची 1 के अनुच्छेद 47 के तहत शुल्क के साथ प्रभार्य है, लेकिन इस अनुच्छेद की सामान्य छूट को ध्यान में रखते हुए दायित्व पत्र पर शुल्क नहीं लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि दायित्व पत्र एक दस्तावेज है, जिस पर शुल्क नहीं लगता है।

भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क के साथ चार्ज किए जाने वाले और निष्पादित किए गए दस्तावेज पर निष्पादन से पहले या उस समय पर धारा 117 के अधीन स्टाम्प लगाई जानी चाहिए: यदि दायित्व पत्र का इरादा बीमाधारक या बीमा कराने की पेशकश करने वाले व्यक्ति द्वारा दावा करने के लिए किया जाना है और इसलिए इसे पॉलिसी के रूप में माना जाना है, तो दायित्व पत्र पर उस पॉलिसी के लिए अपेक्षित स्टाम्प के साथ उचित स्टाम्प लगाना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यदि उनका ऐसा इरादा नहीं है और वे चाहते हैं कि दायित्व पत्र दायित्व पत्र के रूप में ही

रहे, जिसके आधार पर केवल उसमें उल्लिखित पॉलिसी का वितरण लागू किया जा सकता है, तो वे सामान्य अपवाद का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें इस पर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर स्टाम्प लगाने या न लगाने का निर्णय उस समय लिया जाना है जब इसे निष्पादित किया जाना है। यदि इस पर स्टाम्प नहीं लगी है, तो यह केवल एक दायित्व पत्र है जिसके लिए किसी स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता नहीं है। यह एक वैध और संपूर्ण दस्तावेज़ है। अधिनियम में इसके बाद किसी भी पक्ष या किसी लोक सेवक द्वारा इस पर स्टाम्प लगाने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। सामान्य अपवाद के प्रावधान में नियम से किसी दावे या किसी अन्य उद्देश्य के लिए दायित्व पत्र के उपयोग के बारे में, जब उस पर ऐसी पॉलिसी के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प होता है, तो इसका मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि इसके निष्पादन के बाद कोई भी इससे लाभ पाने वाली पार्टी बस उस पर अपेक्षित स्टाम्प लगा सकती है और उसके बाद किसी भी दावे को लागू करने या किसी भी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग कर सकती है। परंतुक का ऐसा निर्माण सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा और अधिनियम के उद्देश्यों में से एक को विफल कर सकता है। यह सच है कि अधिनियम एक राजस्व उपाय है, लेकिन साथ ही दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाने से लेनदेन और दस्तावेज़ की तैयारी को एक निश्चित औपचारिकता मिलती है। दायित्व पत्र को स्टाम्प शुल्क से छूट दी

गई है क्योंकि बिना स्टाम्प लगे होने के कारण इसका उपयोग पॉलिसी के वितरण को लागू करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि दायित्व पत्र को वास्तविक पॉलिसी में बदलने के लिए ऐसे दस्तावेज़ पर बाद में स्टाम्प लगाना, अनिश्चित घटना घटित होने के कारण लाभ पाने वाली पक्ष की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, तो यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा क्योंकि इससे जिस पक्ष को अपेक्षित स्टॉप तय करने से लाभ मिलना निश्चित है, जिसका मूल्य उसके द्वारा प्राप्त होने वाले मौद्रिक लाभ की तुलना में नगण्य है, उसे आवश्यक स्टॉप तय करने से कोई आपत्ति नहीं होगी और सामान्य तौर पर पक्षकार दस्तावेज़ निष्पादित होने पर पहली बार में स्टॉप के भुगतान से बचना चाहेंगी। इसके अलावा, दायित्व पत्र बीमाकर्ता द्वारा जारी किया जाता है और, अनिश्चित घटना घटित होने पर, बीमा करने वाला व्यक्ति ही अपेक्षित स्टाम्प लगाना चाहेगा और उसके बाद पॉलिसी की सीमा के भीतर हुए नुकसान की राशि का दावा करना चाहेगा। इस प्रकार दायित्व पत्र के निष्पादक को एक नीति के रूप में दस्तावेज़ की शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जब दस्तावेज़ को निष्पादित करने के समय उसका ऐसा बाध्य होने का इरादा नहीं था। जब निष्पादन के समय दायित्व पत्र पर स्टाम्प नहीं लगाई जाती है, तो दोनों पक्ष इसके आधार पर मौद्रिक रूप से जो हासिल करना चाहते हैं, उसे खो देते हैं। बीमा कराने वाला व्यक्ति पॉलिसी जारी करने से

पहले होने वाले किसी भी नुकसान की वसूली खो देगा। बीमाकर्ता-कंपनी सीमित अवधि के लिए प्रीमियम की वसूली खो देती है, यानी, कवर नोट की तारीख और प्रस्तावक को नुकसान होने की तारीख के बीच की अवधि। दोनों पक्ष दायित्व पत्र पर स्टाम्प न लगाकर और इस प्रकार इसे एक दस्तावेज न बनाकर नुकसान का जोखिम उठाते हैं, जिस पर पॉलिसी के वितरण के अलावा अन्य दावा आधारित हो सकता है।

इस संबंध में, धारा 47 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो कुछ परिस्थितियों में कुछ दस्तावेजों पर बाद में स्टाम्प लगाने का प्रावधान करता है। लेकिन यह भी कुछ दस्तावेजों से संबंधित है, जो शुल्क के साथ प्रभार्य होने के बावजूद धारा 35 के परन्तुक (अ) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

धारा 62(1)(ख) गवाह के रूप में शुल्क के साथ प्रभार्य और खंड (ए) में शामिल नहीं किए गए किसी भी दस्तावेज को विधिवत मुद्रांकित किए बिना निष्पादित या हस्ताक्षर करना दंडात्मक बनाता है। आवश्यक स्टाम्प के साथ दायित्व पत्र पर किसी भी बाद की स्टाम्प लगाने से पार्टियों को धारा 62(1)(ख) द्वारा निर्धारित दंड से बचने में मदद मिलेगी, चूंकि दायित्व पत्र शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है और बाद में मुद्रांकन का मतलब यह होगा कि यह बीमा की पॉलिसी बन जाती है, एक दस्तावेज जिसे उचित रूप से मुद्रांकित होने के कारण लागू किया जा सकता है।

धारा 29 में प्रावधान है कि किसी विपरीत समझौते के अभाव में, अग्नि-बीमा की पॉलिसी के मामले में उचित स्टॉप प्रदान करने का खर्च पॉलिसी जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा। हालाँकि अधिनियम में इस बात का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है कि दस्तावेज़ पर स्टाम्प कौन लगाएगा, धारा 62 के प्रावधानों को देखते हुए, शुल्क के साथ लगने वाले दस्तावेज़ पर स्टाम्प न लगाने के लिए पीड़ित होने वाला व्यक्ति निष्पादक है। बीमाकर्ता दायित्व पत्र पर बाद में स्टाम्प लगाना पसंद नहीं करेगा और विशेष रूप से तब जब अनिश्चित घटना घटी हो। ऐसी परिस्थितियों में आश्वासनकर्ता द्वारा बाद में स्टाम्प लगाने पर विधानमंडल द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा, अनुच्छेद 47 के सामान्य अपवाद के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, बिना स्टाम्प लगे दायित्व पत्र के तहत कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि वादी को देय कथित किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई मुकदमा संस्थित नहीं किया जा सकता है। जब मुकदमा ही संस्थित नहीं किया जा सकता तो अधिनियम की धारा 35(अ) के तहत कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह कार्रवाई मुकदमा शुरू होने के बाद और दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार करने के समय की जानी है।

अपीलकर्ता के लिए यह सुझाव दिया गया है कि सामान्य अपवाद के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि दायित्व पत्र को स्टांप शुल्क से छूट दी गई थी क्योंकि विधायिका का इरादा नहीं था कि स्टांप शुल्क का भुगतान दो बार किया जाए, एक बार दायित्व पत्र पर और दूसरी बार जब पॉलिसी जारी की गई तब यदि विधायिका वास्तव में ऐसा चाहती थी, तो वह बस यह प्रदान कर सकती थी कि यदि दायित्व पत्र पर अपेक्षित स्टाम्प लगी है, तो पॉलिसी पर स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, विधायिका ने अलग तरह से बात की। इसने दायित्व पत्र को छूट दे दी और प्रावधान किया कि बिना स्टाम्प के दायित्व पत्र का उपयोग केवल उसमें उल्लिखित पॉलिसी के वितरण को लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए छूट के पीछे का उद्देश्य बहुत सीमित उद्देश्य प्रतीत होता है जिसके लिए दायित्व पत्र का उपयोग किया जा सकता है। विधायिका को एक दायित्व पत्र के बारे में पता था जिसमें आम तौर पर ऐसी सामग्री होती है जो इसे एक सीमित अवधि के लिए पॉलिसी बनाती है और इसलिए आगे प्रावधान किया गया है कि इसका उपयोग किसी दावे के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है यदि उस पर पॉलिसी के लिए अपेक्षित स्टांप हो। उचित निष्कर्ष यह है कि विधायिका ने इसे संबंधित पक्षों के विवेक पर छोड़ दिया है कि दायित्व पत्र पर स्टाम्प लगाई जाए या नहीं, जैसा कि वे इसका उपयोग करना चाहते हैं, और इसलिए

प्रावधान को इस आशय से समझना गलत होगा कि किसी भी परिस्थिति में दस्तावेज़ पर किसी भी बाद की स्टाम्प लगाने से दस्तावेज़ की प्रकृति बदल जाएगी और यह उन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हो जाएगा जिनके लिए निष्पादन के समय इसका उपयोग करने का इरादा नहीं था।

ट्राईकैमजी दामजी एंड कंपनी बनाम विरजी कांजी के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले पर अपीलकर्ता के लिए भरोसा रखा गया है।

उस मामले में वादी ने समुद्री-बीमा के अनुबंध के संबंध में बिना स्टाम्प लगे सुरक्षा नोट के आधार पर नुकसान का दावा किया था। मार्टन जे. ने माना कि अभिव्यक्ति 'जब तक कि ऐसे पत्र या वचनबंध पर ऐसी नीति के लिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प न हो' अनुच्छेद 47 का सामान्य अपवाद का अर्थ है निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय स्टाम्प लगाना, जैसा कि धारा 17 में प्रदान किया गया है और वह धारा 35 (ए) को अनुच्छेद 47 में सामान्य अपवाद के परंतुक में स्पष्ट निर्देश के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि उनके विचार को अपीलीय पीठ द्वारा गलत तरीके से स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें सुरक्षा नोट को एक पॉलिसी माना गया जिसे अधिनियम की धारा 35 के तहत आवश्यक कार्रवाई के बाद साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हमने पहले ही वर्तमान मुकदमे में सुरक्षा नोट को पॉलिसी नहीं माना है।

इसलिए मेरी राय है कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि अंतरिम संरक्षण नोट, जिसके निष्पादन के समय एक पॉलिसी के रूप में उचित रूप से स्टाम्प नहीं लगाई गई थी, बाद में अधिनियम की धारा 35(a)के प्रावधानों के अनुसरण में अपेक्षित टिकटों के साथ स्टाम्प नहीं लगाई जा सकती और अपीलकर्ता अपने दावे को मुकदमे में अंतरिम संरक्षण नोट पर आधारित नहीं कर सकता है। तदनुसार, मैं इस न्यायालय और उच्च न्यायालय की अपील को हर्जे के साथ खारिज करता हूँ और उच्च न्यायालय की डिक्री को इस आशय से संशोधित करता हूँ कि 93,628-8-0 रुपये के मुकदमा को विचारण न्यायालय में आनुपातिक हर्जे के साथ खारिज किया जाए।

आदेश

'बहुमत की राय के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है, वादी अपीलकर्ता के पक्ष में 93,628/8/- रुपये की डिक्री पारित की जाती है, और विद्वान विचारण न्यायाधीश के निर्णय की तारीख से उस पर छह प्रतिशत की दर से हर्जा सहित ब्याज लगाया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संजय कुमार गुप्ता (आर०जे०एस०) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।